RAJYA SABHA

Friday, the 25th May, 1990/4th *Jyaistha.* 1912 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock Mr. Chairman in the chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक एककों के उच्च अधिकारियों को निलंबित किया जाना

***341. श्रीमती वीणा वर्मा :†**
श्री कपिल वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के दो उर्वरक एककों तथा सहकारी क्षेत्र के एक उर्वरक एकक के तीन उच्च अधिकारी हाल में निलम्बित किए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

केन्द्रीय क्रय समिति, जिसे सरकारी/सहकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के लिए जूट और एच.डी.पी.ई. के बोरों की खरीद की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था, के माध्यम से जूट और एच.डी.पी.ई. के बोरों की खरीद के संबंध में गम्भीर आरोप लगाए गए थे । सी.बी.आई. से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय क्रय समिति के सदस्यों ने खरीद के सौदे में आपराधिक षडयंत्र में भाग लिया है । जिसके लिए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और निजी आपूर्तिकर्ताओं का अनुचित पक्ष लिया जिससे विभिन्न सरकारी/सहकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों को पर्याप्त आर्थिक हानि हुई । सी.बी.आई. द्वारा और आगे जांच किए जाने तक सरकार ने कृषक भारती को-आपरेटिव लि० (कृभको) के प्रबन्ध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन एफ एल) के प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आरसीएफ) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जो सभी केन्द्रीय क्रय समिति के सदस्य थे, को निलंबित करने के आदेश जारी किए थे ।

सी.बी.आई. ने उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं ।

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, the statement says that the CBI inquiry has shown that substantial pecuniary losses have been caused to the various public or co-operative fertilizer companies. I would like to know the total value of the purchases made on the recommendations of the Central Purchase Committee by these companies and the cost paid for each bag. I would also like to know how far it was higher than the market price. The more important thing, which I would like to know, is what the total loss is which has been caused to these companies because of this conspiracy.

श्री नितिश कुमार : सभापति जी, पूरा विवरण तो सी०बी०आई० की पूरी इन्क्वायरी के बाद सामने आएगा, लेकिन अभी प्रारम्भिक रूप से जो बात सामने आई है, वह लगभग पचास पैसे प्रति बैग के हिसाब से अधिक दाम दिया गया जूट बैग का और लगभग एक रुपया प्रति बैग के हिसाब से एच०डी०पी०ई० बैग का अधिक दाम दिया गया था ।

कम से कम अनुमान ऐसा लगाया गया है कि एक करोड़ से अधिक का इस तरह से नुकसान हुआ है ।

† सभा में यह प्रश्न श्रीमती वीणा वर्मा द्वारा पूछा गया ।

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, there was a fourth member of the Central Purchase Committee Mr. M. H. Avadhani, the Chief Executive of the IFFCO. He was a member till February last when he was asked to quit. What was his role in this conspiracy since he vas on this Committee for several months? Are there any charges against him by the CBI and, if so, what action has been taken against him? Also, does his name figure in the charge-sheet?

श्री नितिश कुमार : सभापति जी, अवधानी को इफको के बोर्ड के एक रेज्योल्यूशन के द्वारा हटा दिया गया है।

उन पर इसके अलावा भी कई आरोप थे। सी०बी०आई० के एफ०आई०आर० में उनका नाम आया है। यह पहली जो प्रारंभिक इंक्वायरी हुई थी, उसमें भी उनका नाम आया था। तो उनको इस साल 9 मार्च को सर्विस से भी टर्मिनेट कर दिया गया है। उनके ऊपर कई और आरोप लगे थे। अवधानी को सैंट्रल पर्चेज कमेटी से पिछले ही साल सितम्बर से हटाया गया था और उनकी जगह पर दूसरे सदस्य इफको से गये थे।

श्री सुरेश कलमाडी : उन पर सी0बी0 आई0 की इंक्वायरी है कि नहीं ?

श्री नितिश कुमार : हां, उन पर तो इंक्वायरी है ही। नेम्ड एक्यूज्ड है एफ० आई०आर० जो लाज हुआ है, उसमें उनका भी नाम है।

श्री कपिल वर्मा : आरोप पत्र कहा क्यों नहीं ? The statement says that the members of the Central purchase Committee have entered into a criminal conspiracy in pursuance of which they misused their official position and showed undue favours to private suppliers. Now, my question is this. Has the C.B.I, in its preliminary report, indicated the extent of form of corruption involved in this conspiracy? Are the press reports correct that the C.B.I. suspects—This is in all the Delhi papers.— that the kickbacks totalling Rs. 16 crores were involved? Would the Government confirm it? Secondly, does the C.B.I, report indicate any involvement of Shri R. K. Anand, Joint Secretary of the Fertilisers Department of the Government of India, in this controversy? He has now been shifted. What action has been taken in connection with the deal of the Fertilisers Department with Morroco for the import of 1.85 million tonnes of phosphoric acid in which this officer figures? Is the Government looking into the serious charges of corruption, nepotism and all kinds of charges. What action has been taken against the Managing Director of KRIBHCO who has now been chargsheeted ? Is the Government aware of a deal in which gunny bags worth 1.40 crores were supplied in violation of all norms and without taking administrative permission?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, सी०बी०आई० ने प्रारंभिक जांच की है और इस मामले में एक एफ०आई०आर० भी दर्ज किया है। जांच चल रही है। विस्तृत ब्यौरा जांच के बाद सामने आएगा। दूसरे भी जो मामलों की चर्चा माननीय सदस्य ने की है उसके संबंध में उप प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था 28 दिसम्बर को कि इन मामलों की सी०बी०आई से जांच कराई जाए और प्रधान मंत्री ने सारे मामले को 10 जनवरी को सी०बी०आई० को रैफर कर दिया। सी०बी०आई० ने इस एक मामले में अभी एक प्रारंभिक रिपोर्ट दिया है और उसके बाद इनके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई और एफ०आई०आर० भी दर्ज किया गया। अन्य मामलों के बारे में अभी सी०बी० आई० के प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो सकी है या उसके संबंध में इस प्रश्न के माध्यम से सूचना दे पाना अभी कठिन होगा।

श्री कपिल वर्मा : ज्वाइंट सेक्रेटरी का नाम सी०बी०आई० ने अभी लिया है कि नहीं लिया है ?

श्री नितिश कुमार : इस केस में सी० बी०आई० ने ज्वाइंट सैक्रेटरी का नाम नहीं लिया है। इसमें पांच लोगों का नाम लिया है जिन पांचों लोगों पर सी०बी० आई० एफ०आई०आर० दर्ज किया है।

श्री कपिल वर्मा : यह मोरक्को वाली डील में क्या हुआ है ?

श्री नितिश कुमार : इससे उसका संबंध नहीं है। इससे संबंधित वह बात नहीं है। जो आपने प्रश्न किया है उसके संबंध में यह सूचनाएं हैं।

श्री कपिल वर्मा : यह ज्वाइंट सेक्रेटरी उसमें इनवाल्व था ?

श्री नितिश कुमार : इसकी सूचना अलग से दी जाए और जो माननीय सदस्य बतला रहे हैं इसके बारे में भी अलग से हम लोग उसको देख लेंगे और उसकी जांच करायेंगे जो यह माननीय सदस्य अभी प्वायंट आउट कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह तीन सरकारी और सहकारी कंपनियां हैं और उन्होंने दोषी बताया है कि पांच आदमी हैं तो इन तीनों कंपनियों के प्रबन्धक और चेयरमैन अतिरिक्त दो और कौन हैं ? तथा निजी आपूर्तिकर्ताओं का जो उन्होंने पक्ष लिया था वह कितने निजी आपूर्तिकर्ता थे, उनके भी नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नितिश कुमार : यह तीनों जो सस्पेंड किए गए, हैं उनके अलावा नाम आया है एम०एच० अधधानी, उस समय यह इफको के एम० डी० थे और दूसरा नाम महादेव खड़किया का आया है जो अशोक लेमिनेटर्ज के हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : निजी कंपनियों के बारे में ?

श्री नितिश कुमार : निजी कंपनियां तो अनेक हैं जिनको यह काम दिया गया था।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, whether it is public sector companies or private sector companies producing fertilisers and whether it is cost escalation or inefficiency, the Indian farmer is compelled to pay five times more to get the same quantity of fertilisers than his counterpart in Japan and two to three times more than his counterpart in Bangladesh and Pakistan. What steps would the Government like to take to reduce the priees of fertilisers to bring them on par with the prices that the other faraokig eom-munit'es are paying in other parts of the world.

श्री नितिश कुमार : यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार सबसिडी देती है और पिछले साल सबसिडी दिया है। इस बार भी चार हजार करोड़ रुपये से अधिक एक साल में सबसिडी सरकार ने फर्टीलाइजर सैक्टर में दी है। सिर्फ इसलिए कि किसानों को कम कीमत पर फर्टीलाइजर मिल सके।

Dr. YELAMANCHILI SIVAJI : In spite of the subsidy we are paying more.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, यह तो अच्छा काम किया है कि इन लोगों का सस्पेंशन किया गया और मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन एक बात जो हम लोग देख रहे हैं, वह यह है कि सरकार के नोटिस में जब बात आती है और उस पर कार्यवाही की जाती है, उस में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और तब तक उन पर कोई इफेक्टिव कार्यवाही नहीं हो पाती है। कभी-कभी तो लोग रिटायर हो जाते हैं, मर जाते हैं और बाद में छोड़ दिया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में सरकार के नोटिस में यह बात कब आई और आपने एक्सन कब लिया ? अभी तो सस्पेंशन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय लगा और

दूसरी बात क्या सरकार कोई इन-बिल्ट सिस्टम तैयार करेगी जिस में इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों पर जल्द-से-जल्द कार्यवाही की जा सके । इन्हीं दो बिंदुओं पर मैं मंत्री जी से जवाब चाहूंगा ।

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, जब उप-प्रधान मंत्री और कृषि, मंत्री के नोटिस में यह बात आई तो जैसाकि मैंने पहले बताया कि उन्होंने 28 दिसम्बर को प्रधान मंत्री को पत्र लिखा कि इस विभाग में ऐसे कुछ घोटाले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए ।

श्री चतुरानन मिश्र : सरकार के नोटिस में तो बात पहले ही आ गयी होगी, प्रधान मंत्री के बाद में आई होगी ?

श्री नितिश कुमार : इस सरकार के नोटिस में जब बात आई, उप-प्रधान मंत्री के ही नोटिस में आई तो उन्होंने तत्काल प्रधान मंत्री को 28 दिसम्बर को पत्र लिखा । प्रधान मंत्री के कार्यालय से सी०बी०आई० को 10 जनवरी को चला गया और सी०बी०आई० ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की । इंक्वायरी से जो उन को मिला, उस आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंशन की कार्यवाही की गयी । दिनांक 15 मई को सी०बी०आई० ने एफ०आई०आर० दर्ज की । सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज तमाम सम्बद्ध लोगों के घर सर्च हो रही है ताकि इस के बारे में फर्दर डाक्युमेंट्स मिल सकें । आज यह सभी जगह पर प्रोग्रेस में है ।

श्री चतुरानन मिश्र : कोई इन बिल्ट सिस्टम बनाएगी सरकार ताकि ऐसे मामलों में जल्द-से-जल्द हम निर्णय ले सकें क्योंकि अभी जो सिस्टम है वह बड़ा टाइम कंजूमिंग है । इसलिए क्या आप कोई इन बिल्ट सिस्टम बनाएंगे जिससे कि कम-से-कम अवधि में ऐसे मामलों का निष्पादन हो सके ?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, यह तो नीति विषयक मामला है और अभी जो प्रचलित पद्धति है उसके हिसाब से यह हो रहा है । ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, यह सजेशन फॉर एक्शन है । ... (व्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र : इतना तो कह दें कि विचार करेंगे ?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, यह सजेशन फॉर एक्शन है और स्वाभाविक है कि जब माननीय सदस्य और इतने वरिष्ठ सदस्य कोई सुझाव देते हैं तो उनके सुझावों का लाभ सरकार अवश्य उठाएगी ।

SHRI K.K. VEERAPPAN: My first question is whether there is any proposal for starting any other fertilizer unit *by* the Central Government in Tamil Nadu. Second, for how long the Managing Director has been in the post? Third, to which period the scandal relate?

श्री नितिश कुमार : महोदय, पहले का संबंध इस से नहीं । दूसरे का जहां तक सवाल है, यह कमेटी गठित की गयी थी, 1988 में आर्डर किया उस समय के मिनिस्टर आफ स्टेट फर्टीलाईजर ने और उसके आधार पर 10 जनवरी को यह कमेटी गठित हुई और उस ने काम करना शुरू किया । तो 89 के पीरियड के यह करप्शन चार्जेज हैं ।

KUMARI CHANDRIKA PRE-MJI KENIA: It is said in the reply that a criminal conspiracy was hatched and undue favour was shown to the praivate party. I would like to know from the hon. Minister who these private suppliers are and whether any action has bean taken against these private suppliers because a *prime facie* case has been registered with the C.B.I. I would like to know whether the private suppliers have also been taken to task.

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, जो प्राइवेट सप्लायर्स हैं, वे कई हैं । इनमें यह अशोक लेमिनेटर्स के खड़किया हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है क्योंकि सबसे ज्यादा वे इंटरएक्ट कर रहे थे सी०पी०सी० के मेम्बर और जो प्राइवेट इसमें हैं पार्टीज, उनके बीच में । तो सबसे

अधिक दोषी उनको मानते हुए उन पर भी कार्यवाही हो रही है ।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : सी०बी०आई० इन्क्वायरी में वे हैं ?

श्री नितिश कुमार : जी हां, सी०बी० आई० इन्क्वायरी में है । अशोक लेमिनेटर्स के खड़किया जो हैं, उनका नाम एफ० आई०आर० में है , प्राइमा फेसी केस उन पर बना है ।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : बाकी नाम बता दीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : नाम बताने से क्यों डरते हैं ?

श्री नितिश कुमार : मिस्टर खड़किया, बताया न ।

श्री राम अवधेश सिंह: यह तो एक का नाम बताया है, आपके अनुसार ऐसे तो कई आदमी हैं ।

श्री नितिश कुमार : एक मुरलीधर रतन लाल एक्सपोर्टर कलकत्ता के हैं, ऐसे कई हैं, 40–45 हैं जिन्होंने सप्लाई किया ।

श्री सभापति : ये 40–45 की खबर इनके पास भेज दीजिएगा ।

श्री नितिश कुमार : जी हां, सूचना बाद में दे सकते हैं ।

*342. *[The questioner (Dr. Jinen-der Kumar Jain) was absent. For answer* vide co/s.34-35 infra]

पादप ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा नई किस्मों का विकास

343. **डा० एन० तुलसी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पादप ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा मुख्य फसलों, विशेषतः चावल, गेहूं, दालों तथा तिलहनों के क्षेत्र में अब तक विकसित की गई किस्मों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या ये किस्में पारंपरिक तकनीक द्वारा विकसित ज्यादा पैदावार देने वाली दूसरी किस्मों से बढ़िया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऊतक संवर्धन अनुसंधान द्वारा इन किस्मों को विकसित किये जाने पर कितनी राशि खर्च की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : (क) महोदय, अभी तक पौध टिश्यू कल्चर (ऊतक संवर्धन) तकनीक के द्वारा चावल, गेहूं, दालों तथा तिलहनों की कोई किस्म रिलीज नहीं की गयी हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY : Sir, in the question itsefl I asked how much money has been spent on the Plant Tissue culture technique during the last three years. This question has not been answered. Anyhow, though my first supplementary I am asking this question again. How much money has been spent on the Plant Tissue culture techniue and the conventional technique during the last three years and what is the budget allocation for these two techniques in the current financial year?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, यह टिश्यू कल्चर बायो टेक्नोलोजी का ही एक पार्ट है और बायो टेक्नोलोजी सेक्शन ने इस पर जो काम शुरू किया है, पिछले तीन साल नहीं, लेकिन 1989 में इस पर एलोकेशन